कोटद्वार, रविवार
22 फरवरी 2026
वर्षः 48
अंकः 269 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नगेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

मुराड़ी पुल के पिलर निर्माण के लिए आठ लाख मंजूर

उत्तरकाशी। सर–बडियार क्षेत्र के दूरस्थ गांव डिंगाड़ी में आयोजित जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने आठ गांव को जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर क्षतिग्रस्त मुराड़ी पुल के निर्माण की मांग की। डीएम प्रशांत आर्य ने पुल के पिलर निर्माण के लिए आठ लाख की धनराशि की स्वीकृति देकर लोनिवि को जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। डिंगाड़ी गांव में विधायक दुर्गेश्वर लाल और डीएम प्रशांत आर्य की मौजदूगी में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। इस मौके पर शिविर में कुल 16 समस्याएं और शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 13 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से स्टाल स्थापित कर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर भूपेंद्र निवासी डिंगाडी ने एपीएल से बीपीएल राशन कार्ड बनाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने गंगरालीझडिंगाडी– किमडारझसरगांव तथा किमडारझपौंटीझगौलझछानिका सड़क मार्गों की स्थिति की जानकारी पीएमजीएसवाई से ली। साथ ही किमडार–कंसलों मार्ग एवं गांव के नीचे हुए भूस्खलन को लेकर विस्थापन और सुरक्षात्मक कार्य की मांग की गई।इस पर डीएम ने भू–वैज्ञानिक एवं सिंचाई विभाग को 26 एवं 27 फरवरी को संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिविर में विधायक दुर्गेश्वर लाल ने क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए 28 लाख की घोषणा की।

गुलदार ने बाइक सवार पर मारा झपटा, ग्रामीण घायल

नई टिहरी। मणि–कुमराड़ा–स्यांयू सड़क पर बीते शुक्रवार रात्रि को गुलदार ने एक बाइक सवार व्यक्ति पर अचानक हमला कर दिया। हमले के दौरान वह गंभीर घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो गुलदार भाग गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। बल्डोगी निवासी मकान सिंह बीते शुक्रवार को बाइक से कुमराड़ा से अपने गांव की ओर जा रहे थे। कुछ दूर पहुंचते ही गुलदार ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इससे बाइक सवार नीचे गिर गया। मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने शोर मचाकर गुलदार को वहां से भगाया। घटना में गुलदार के नाखूनों के हमले में मकान सिंह गंभीर घायल हो गए। उन्हें निजी वाहन से उपचार के लिए सीएचसी चिन्यालीसौड़ पहुंचाकर वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।

कार अनियंत्रित होकर पांच सौ फीट खाई में गिरी, चालक कूदा

देहरादून। देहरादून से मसूरी अते समय अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में जा गिरी। चालक ने वाहन से कूद कर जान बचाई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची ने जांच की। मसूरी पुलिस को 112 कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली की मसूरी देहरादून मार्ग पर मसूरी झील से करीब पांच सौ मीटर भट्टा गांव की तरफ एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली से तत्काल पुलिस बल आपदा उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचा। साथ ही फायर सर्विस एवं एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि टैक्सी वाहन सड़क से लगभग 500 फीट नीचे खाई में गिरा हुआ है। वाहन चालक नेहाल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम रामपुर कला थाना सहसपुर, तहसील विकासनगर चला रहा था। वह देहरादून से मसूरी की तरफ आ रहा था। मसूरी झील के पास वाहन अनियंत्रित होने पर चालक पहले ही वाहन से कूद गया था, जिसके कारण उसे किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई। ड्राइवर का फोन व कपड़ों से भरा बैग पुलिस उनके सुपुर्द किया गया। मौके पर पुलिस द्वारा यातायात को सुचारू कराया गया।

चरस तस्करी के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास

रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आशुतोष कुमार मिश्र ने चरस तस्करी के दोषी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.10 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। 28 फरवरी 2015 को खटीमा क्षेत्र के ग्राम रतनपुर से पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति परचून की दुकान की आड़ में चरस की तस्करी कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने रतनपुर जसारी स्थित दुकान पर छापा मारा।

मौसम खुला तो मैदान से लेकर पहाड़ तक चढ़ा पारा

आने वाले दिनों में फिर बारिश–बर्फबारी

देहरादून। दो दिन बाद प्रदेशभर में मौसम खुला तो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खासकर मैदानी इलाकों में दिन के समय गर्मी का अहसास हुआ। शनिवार को भी प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को दून में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री इजाफे के साथ 28.2 डिग्री दर्ज किया गया।

जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से सामान्य से दो डिग्री बढ़ोतरी के साथ 11.6 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी रहा। आने वाले दिनों की बात करें तो रविवार से एक बार फिर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा।

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। खासकर प्रदेश के तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है।

देशी–विदेशी पर्यटकों की आमद से फिर लौटी रौनक

ऋषिकेश। मौसम में गर्माहट बढ़ने के साथ देश–दुनिया से पर्यटकों की भीड़ ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में जुटनी शुरू हो गई है। विदेशी पर्यटक यहां योग, आध्यात्म और सुकून की तलाश में पहुंच रहे हैं, जबकि देसी पर्यटक साहसिक पर्यटन राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कैंपिंग के लिए आ रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से निर्भर कारोबारियों के चेहरों पर भी मुस्कान दिख रही है।

इन दिनों ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है। रसिया, अमेरिका, जर्मनी समेत विभिन्न देशों से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे सभी क्षेत्र में पर्यटकों की भीड़भाड़ से गुलजार दिख रहे हैं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों से भी पर्यटक आ रहे हैं। इन पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र कौड़ियाला–मुनिकीरेती ईको टूरिज्म जोन में राफ्टिंग बना हुआ है। राफ्टिंग की ओर खींचाव सहासिक पर्यटन के रोमांच का अनुभव के साथ गर्म होता मौसम भी है। वह दिन में चटक धूप के बीच नीरगड्ड और पटना वाटर फाल तक पहुंच रहे हैं।

दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा कुंभ मेला : धामी

श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कुंभ मेला तैयारियों की समीक्षा

जयन्त प्रतिनिधि।

हरिद्वार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हरिद्वार में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में अगले वर्ष आयोजित होने वाला कुंभ मेला दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक होगा। मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस महाआयोजन की व्यवस्थाओं में कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुंभ मेले से संबंधित कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। मेला नियंत्रण भवन, हरिद्वार में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने मेले से संबंधित सभी कार्य आगामी अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेले के लिए सभी प्रमुख स्थायी कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा अस्थायी कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर उन्हें भी समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। जोन एवं सेक्टर स्तर पर की जाने वाली तैयारियों को तय

लक्ष्यों और समय सीमा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न करें। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराने को कहा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन तथा स्नान की समुचित व्यवस्था की जाए। संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्नान, आवागमन एवं ठहराव के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्य में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बीमार श्रद्धालुओं को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए बोट एवं बाइक एंबुलेंस की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए साधु-संतों, अखाड़ों, जनप्रतिनिधियों तथा धार्मिक एवं स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाए और उनके सुझावों को ध्यान में रखकर कार्य किए जाएं। उन्होंने कुंभ मेले में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती पर जोर दिया। साथ ही साइबर सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था तथा रेस्क्यू कार्यों के लिए दक्ष कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। स्थायी कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुंभ क्षेत्र में निर्मित सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट कराया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत समय पर पूर्ण की जाए। गंगा नदी के घाटों के अनुरक्षण हेतु यदि गंग नहर के क्लोजर की आवश्यकता हो तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मेलाधिकारी सोनिका, सचिव, शहरी विकास विभाग नितेश कुमार झा, सचिव, लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पाण्डे; आयुक्त, गढ़वाल मंडल विनय शंकर पाण्डेय, सचिव, पेयजल रणवीर सिंह चौहान, सचिव, सिंचाई युगल किशोर पंत, सचिव, पर्यटन धीराज गर्ब्याल, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव, बैठक में मेयर हरिद्वार किरन जैसल, विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा, विधायक हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत, विधायक ज्वालापुर रवि बहादुर आदि मौजूद थे।

उत्तराखंड में आपदा चेतावनी तंत्र होगा मजबूत

9 जिलों में लगेंगे एडब्लूएस, 3 में डाप्लर राडार

देहरादून। आपदा जोखिम को कम करने और समय पर सटीक चेतावनी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम को सशक्त बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। इस कड़ी में नौ जिलों में आटोमैटेड वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) और तीन जिलों में डाप्लर राडार लगाए जाएंगे। इससे मौसम और संभावित आपदा की पहले ही जानकारी मिल सकेगी, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मददगार होगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार रक्षा भू–स्थानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) के सहयोग से उत्तरकाशी व टिहरी जिले में आठ–आठ, पौड़ी में सात, देहरादून में पांच, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर में तीन–तीन, अल्मोड़ा में दो और नैनीताल व हरिद्वार जिले में एक–एक एडब्ल्यूएस स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली जिलों में से किन्हीं तीन में डाप्लर राडार लगाए जाएंगे। संबंधित जिलों को इसके लिए भूमि चयनित कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एडब्लूएस से जहां मौसम से जुड़ी सटीक व त्वरित जानकारी प्राप्त होगी, वहीं डाप्लर राडार से वर्षा, बादल और मौसम की गतिविधियों पर रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इस बीच आपदा प्रबंधन सचिव ने शनिवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में हुई बैठक में सभी जिलों के आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र के एनडीएमआईएस पोर्टल पर आपदा मद में हुए खर्च का पूरा विवरण शीघ्र अपलोड करने के निर्देश दिए। बैठक में आपदाओं के दौरान लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान सचिव सुमन ने कहा कि जिन मामलों में कार्यवाही लंबित है, उनके प्रस्ताव जल्द शासन को भेजे जाएं। वर्ष 2025 में आपदाओं के दौरान मृत नेपाली मूल के लोगों को आर्थिक सहायता और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों की समीक्षा में सचिव ने जिलों को ऐसे लंबित प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा। ताकि, केंद्र के स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए पैरवी की जा सके।

बरातियों पर बदमाशों ने बरपाया कहर: महिलाओं पर भी बरसाए लाठी–डंडे

नई दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पालम विहार थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को सेक्टर–22बी स्थित सामुदायिक केंद्र में पहुंचे बरातियों पर कुछ युवकों ने लाठी–डंडों से हमला कर दिया। बरातियों के साथ मारपीट करने की सूचना मिलते ही पालम विहार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक हमलावर युवक मौके से भाग चुके थे। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है।

गाड़ी को साइड देने पर हुआ विवाद

मामले में विवाद तब हुआ जब झाड़सा गांव से वाल्मीकि समाज की बरात मोलाहेड़ा गांव में गई थी। बरात की चढ़त के दौरान उसमें शामिल लोग नाच–गाने व गाजे–बाजे के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी में सवार युवकों का बरातियों के साथ गाड़ी को साइड देने पर विवाद हो गया।

बरातियों को धमका कर चले गए बदमाश

दूल्हे के रिश्तेदार किशन लाल ने बताया कि गाड़ी में सवार युवकों ने बरातियों को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद युवक मौके से चले गए। कुछ देर बाद युवक अन्य साथियों को लेकर सामुदायिक केंद्र पहुंचे।

दिल्ली को दहलाने की फिराक में लश्कर–ए–तैयबा

आईईडी हमले की साजिश, लाल किला और चांदनी चौक का मंदिर निशाने पर

देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। खुफिया जानकारी के अनुसार, आतंकी संगठन लश्कर–ए–तैयबा दिल्ली के लाल किले के आसपास और चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर में बम धमाके की फिराक में हैं। यह अलर्ट पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई एक मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने की मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है।

खुफिया सूत्रों ने बताया कि लश्कर–ए–तैयबा संगठन आईईडी के जरिए हमला करने की साजिश रच रहा है। विशेष रूप से, चांदनी चौक इलाके में स्थित एक मंदिर को संभावित लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए एक मस्जिद विस्फोट के बाद भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। खुफिया इनपुट के अनुसार, लश्कर–ए–तैयबा देश भर के प्रमुख मंदिरों को भी निशाना बना सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल इस आतंकी संगठन के निशाने पर हैं।

खुफिया सूत्रों ने कहा, 'दिल्ली में लाल किले के सामने ब्लास्ट का अलर्ट है। आतंकवादी चांदनी चौक में एक मंदिर को निशाना बना सकते हैं। लश्कर–ए–तैयबा आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मस्जिद में हुए विस्फोट के बाद यह संगठन भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। देश के बड़े मंदिरों को लश्कर–ए–तैयबा निशाना बना सकता है।' बता दें कि दिल्ली में पिछले साल ही 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका हुआ था। जिसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे।

आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 हेतु जिला प्रशासन ने कसी कमर

श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित संचालन हेतु समन्वय बैठक में व्यापक तैयारियों की समीक्षा

जयन्त प्रतिनिधि। रूद्रप्रयाग : आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 22 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो रही है। यात्रा को सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा तैयारियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं, विभागीय दायित्वों, संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राप्त सुझावों पर विस्तृत चर्चा की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ टीम भावना से कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में समयबद्ध उपचारात्मक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा संबंधी कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोनिवि द्वारा सिरोबगड़, बांसवाड़ा, जवाड़ी बायपास, सिंकिंग जोन सहित अन्य संवेदनशील स्थलों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ रोड को नई टनल से जोड़ने वाले पुल का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने, आवश्यक स्थलों पर भूमि अधिग्रहण कर अतिक्रमण हटाने तथा हटाए गए मलबे का डंपिंग जोन चिन्हित कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 मार्च तक नालियों का निर्माण पूर्ण करने, सड़क किनारे झाड़ियों की कटाई, अनावश्यक सामग्री हटाने तथा ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। रिटर्निंग वॉल, क्रैश बैरियर एवं आवश्यक डायवर्जन स्थलों पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने की बात कही। बैठक में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग नीहारिका तोमर, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रकाश, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष रावत, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग ओंकार पांडे, अधिशासी अभियंता लोनिवि इंद्रजीत बोस, ऊखीमठ आर.पी. नैथानी, एआरटीओ धर्मेंद्र सिंह बिष्ट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

घोड़ा-खच्चरों का बीमा अनिवार्य

यात्रा प्रारंभ से पूर्व प्रभावी बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने तथा बिना पंजीकरण वाले घोड़ा-खच्चरों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। ट्रैक रूट पर तीन चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। बिना पंजीकरण पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सामान ढुलाई में लगे घोड़ा-खच्चरों की सूची पूर्व में जारी की जाएगी तथा पंजीकरण में स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस वर्ष सभी घोड़ा-खच्चरों का बीमा अनिवार्य किया गया है।

अनियंत्रित होकर नाले में पलटी कार, रुड़की के दो युवकों की दर्दनाक मौत

रुड़की। गंगनहर पटरी मार्ग पर शनिवार की तड़के शादी देवबंद में समारोह से रुड़की लौट रहे दो युवकों की कार अनियंत्रित होकर गहरे नाले में जा पलटी। इससे कार सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रुड़की के राजेंद्रनगर निवासी 35 वर्षीय अमन त्यागी और गणेशपुर निवासी 38 वर्षीय सचिन धीमान एक शादी समारोह में देवबंद गए हुए थे। शनिवार तड़के जब वे अपनी कार से वापस रुड़की लौट रहे थे, तभी गंगनहर पटरी पर राणा फैक्ट्री के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे नाले में जा गिरी।

राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी : सीडीएस

गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीडीएस जनरल अनिल चौहान का प्रेरक संबोधन

जयन्त प्रतिनिधि।

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर स्थित स्वामी मनमथन प्रेक्षागृह में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का भव्य स्वागत हुआ। शनिवार को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनरल चौहान ने 'सामरिक सोच एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ सैन्यभूमि भी है। सामरिक सोच को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सामरिक सोच को जन-जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति व्यापक जन-जागरूकता विकसित हो सके।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, विशिष्ट अतिथि शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने दीप प्रज्जवलित कर किया। मुख्य अतिथि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने राष्ट्रीय सुरक्षा का वास्तविक स्वरूप तथा उत्तराखंड का संभावित योगदान क्या हो सकता है विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है, जिसकी शुरुआत विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की दूरदर्शी सामरिक सोच वैदिक साहित्य, चाणक्य नीति और धनुर्वेद जैसी परंपराओं से प्रेरित है, किंतु इतिहास के मुगल और ब्रिटिश कालखंडों में यह दृष्टि कमजोर हुई। आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्रीय तत्व बताते हुए उन्होंने आंतरिक एवं बाहरी खतरों, 1971 के उदाहरण, बदलती युद्ध अवधारणाओं तथा तकनीक-प्रधान संघर्षों का उल्लेख किया। उन्होंने देश की सीमाओं और परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों को भारत की प्रमुख चुनौतियां बताते हुए सुदृढ़ सरकार, मजबूत सेना और रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने उत्तराखंड की सामरिक महत्ता को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, सजग रहने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दिया। कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने अपने स्वागत वक्तव्य में मंचासीन अतिथियों, विधायक, सैन्य अधिकारियों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि वीर भूमि उत्तराखंड, आज मुख्य अतिथि जनरल अनिल चौहान के आगमन से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि इस पावन धरती ने देश को अनेक वीर सपूत दिए हैं।

योग्यता और प्रतिबद्धता ही चयन का आधार

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान पल्लवी उनियाल ने सेना में महिलाओं की भर्ती और उनकी भूमिका को लेकर प्रश्न किया। इस पर जनरल चौहान ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, उसी प्रकार भारतीय सेना के प्रत्येक क्षेत्र में भी महिलाओं को समान अवसर और जिम्मेदारियां प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि योग्यता और प्रतिबद्धता ही चयन का आधार है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं मनीषा सिंह, शुभम, आशीष कुमार आदि ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य सेवा और कैरियर से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका जनरल चौहान ने विस्तार पूर्वक एवं संतोषजनक उत्तर दिया। इस अवसर पर देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कण्डारी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओ.पी. गुसाईं, प्रो. महेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट, प्रो. मोहन पंवार, प्रो. मंजुला राणा, प्रो. एचबीएस चौहान, ब्रिगेडियर विनोद नेगी, कर्नल गौरव बत्रा, मुख्य नियंता प्रो. दीपक कुमार, प्रो. एनएस पंवार, अनीष उज जमान, प्रो. राकेश डोढ़ी, चौरास परिसर के निदेशक प्रो. राजेन्द्र सिंह नेगी, जन संपर्क अधिकारी आशुतोष बहुगुणा, सहित शिक्षक, शोधार्थी, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रकाशन के इंतजार में नरावणे की किताब

सत्ता पक्ष के मुताबिक चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है? बेहतर होगा कि प्रकाशन की मंजूरी अविलंब दी जाए। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावणे की किताब लगभग 21 महीनों से प्रकाशन के इंतजार में है, क्योंकि उसे केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली है। अब उस किताब में वर्णित बातों को लेकर एक अंग्रेजी पत्रिका ने लंबी रिपोर्ट छापी है। उसमें शामिल एक प्रकरण का हवाला विपक्ष के नेता राहुल गांधी लोकसभा में देना चाहते थे। मगर सत्ता पक्ष की आपत्तियों के बीच स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। बहरहाल, कांग्रेस ने उस पूरी रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल कर उसे जनमत के बड़े हिस्से तक पहुंचा दिया है। इसके मुताबिक अगस्त 2020 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कैलाश रेंज की चोटी पर भारतीय फौज के नियंत्रण के बाद चीन ने हमला करने की तैयारी की थी। जब टैंकों समेत चीनी सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ रही थीं, तब तत्कालीन सेनाध्यक्ष नरावणे ने बार-बार रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और विदेश मंत्री को फोन कर जवाबी कार्रवाई के लिए निर्देश मांगे। मगर इस पर घंटों तक टाल-मटोल की गई। आखिरकार प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें निर्देश दिया- जो उचित लगे, वह करें। स्पष्टत: ये प्रकरण वर्तमान सरकार की नेतृत्व क्षमता एवं संकल्प शक्ति को कठघरे में खड़ा करता है। सेना युद्ध संबंधी फौरी (टैक्टिल) फैसले ले सकती है, लेकिन ऑपरेशनल एवं रणनीतिक निर्णय लेने की स्थिति में सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल नरावणे के सामने कई कठिन प्रश्न थे। कोरोना के कारण देश अस्त-व्यस्त था, जिससे मोर्चों पर सहज सप्लाई को लेकर आशंकाएं थीं। फिर युद्ध फैलता, तो विदेश नीति एवं कूटनीति संबंधी उसके परिणामों का आकलन सरकार ही कर सकती थी। मगर उस कठिन घड़ी में केंद्र ने जिम्मेदारी सेनाध्यक्ष पर टाल दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसमें वर्णित मामलों का उल्लेख सदन में नहीं हो सकता। मगर प्रश्न है कि किताब का प्रकाशन किसने रोक रखा है? सरकार के पास कुछ ढकने को नहीं है, तो बेहतर होगा कि वह तुरंत किताब प्रकाशन की मंजूरी दे, ताकि देश तत्कालीन सेनाध्यक्ष के अनुभव उनके ही शब्दों में जान सके।

परमाणु विनाश का खतरा

परमाणु अस्त्रों की होड़ से बचने के लिए संधि की शुरुआत 1970 के दशक से हुई। तब से हमेशा किसी ना किसी संधि का अस्तित्व रहा। मगर अब ऐसा नहीं है। इससे परमाणु हथियारों और मिसाइलों की नई होड़ का रास्ता साफ हो गया है। पांच दशक में ऐसी स्थिति पहली बार आई है, जब दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा टालने की किसी संधि का अस्तित्व नहीं है। चार फरवरी को अमेरिका और रूस के बीच मौजूद न्यू स्टार्ट (स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी) की अवधि समाप्त हो गई। रूस ने अमेरिका से नई संधि होने तक न्यू स्टार्ट की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस तरह अमेरिका और रूस अब असीमित संख्या में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए स्वतंत्र हैं। 2010 में हुई न्यू स्टार्ट के तहत दोनों देशों ने अधिकतम 1550 परमाणु अस्त्रों की तैनाती की सीमा तय की थी। साथ ही प्रावधान था कि दोनों देश एक दूसरे की तैनाती के ठिकानों या अन्य परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कर सकेंगे। इसके तहत अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की संख्या भी तय थी। परमाणु अस्त्रों की होड़ से बचने के लिए संधि की शुरुआत 1970 के दशक से हुई। तब से हमेशा किसी ना किसी संधि का अस्तित्व रहा। मगर अब ऐसा नहीं है। इससे परमाणु हथियारों और मिसाइलों की नई होड़ का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिका की दलील है कि चीन उसके लिए खतरा बन कर उभर रहा है, जो उपरोक्त संधि में शामिल नहीं था।

यूजीसी का नियम सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला

पूरे देश में यूजीसी की ओर से लाए गए समानता के नए नियम पर विवाद हो रहा है। यूजीपी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीच्यूट रेगुलेशन 2026 के नाम से नए नियम जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करना बताया गया है। इस तरह का एक नियम 2012 में बना था, जो पहले से उपलब्ध था। उसमें कुछ बदलाव करके उसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। 2012 के नियम में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को उत्पीड़न से बचाने का प्रावधान किया गया था। अब उसमें अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही महिलाएं और दिव्यांगजनों को भी शामिल किया गया है। महिलाओं और दिव्यांगों में हर वर्ग के छात्र शामिल होंगे।इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के एक छोटे से समूह को पहले से ही अत्याचारी या उत्पीड़क मान कर बाकी लोगों को उससे बचाने का प्रावधान किया गया है। 2012 के कानून में भेदभाव या उत्पीड़न की फर्जी शिकायत करने पर कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग अगर चाहें तो किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है।

अजीत द्विवेदी

राजनीति में कुछ भी अनायास या अनियोजित नहीं होता है और अगर आपको लगे कि कुछ अनायास हो रहा है या अनप्लांड हो रहा है तो समझना चाहिए कि उसे उसी तरह से प्लान किया गया है। यानी उसकी योजना ऐसी बनी है कि वह अनप्लांड लगे। यह बात अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कही थी। पूरी दुनिया की राजनीति पर यह बात समान रूप से लागू होती है। तभी प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर जो कुछ हो रहा है और उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का जो नया नियम लाया गया हैं उसे अनायास हुए नहीं मानना चाहिए। सरकार ने किसी योजना के तहत यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं। उसने सामान्य वर्ग को अलग थलग करने और उसे उत्पीड़क साबित करने का जो नियम बनाया है वह संयोग नहीं है, बल्कि किसी प्रयोग का हिस्सा है।

इस समय पूरे देश में यूजीसी की ओर से लाए गए समानता के नए नियम पर विवाद हो रहा है। यूजीपी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीच्यूट रेगुलेशन 2026 के नाम से नए नियम जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करना बताया गया है। इस तरह का एक नियम 2012 में बना था, जो पहले से उपलब्ध था। उसमें कुछ बदलाव करके उसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। 2012 के नियम में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को उत्पीड़न से बचाने का प्रावधान किया गया था। अब उसमें अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही महिलाएं और दिव्यांगजनों को भी शामिल किया गया है। महिलाओं और दिव्यांगों में हर वर्ग के छात्र शामिल होंगे।

इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के एक छोटे से समूह को पहले से ही अत्याचारी या उत्पीड़क मान कर बाकी लोगों को उससे बचाने का प्रावधान किया गया है। 2012 के कानून में भेदभाव या उत्पीड़न की फर्जी शिकायत करने पर कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग अगर चाहें तो किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वॉयड बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें बदलाव करके यह नियम बनाया गया है कि इसमें सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को रखना अनिवार्य नहीं होगा।

सोचें, क्या इससे भी ज्यादा भेदभाव या असमानता की कोई व्यवस्था हो सकती है? इसमें एक समूह को पहले से अपराधी मान कर उसे सजा के योग्य ठहरा दिया गया है। यह सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला नियम है, जो कानून विरूद्ध है और संविधान विरूद्ध है। यह प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के भी विरूद्ध है। भारत सरकार ने जब अंग्रेजों के जमाने की भारतीय दंड संहिता समाप्त की और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की तो कहा कि अंग्रेजों ने दंड का प्रावधान किया था लेकिन अब सरकार न्याय की व्यवस्था ले आई है।

क्या यही न्याय की व्यवस्था है कि आप एक समूह को पहले से अपराधी मान लेंगे? सवाल है कि आरोप लगाए जाने और दोष सिद्ध होने से पहले किसी को अपराधी कैसे माना जा सकता है? भारत में न्याय की व्यवस्था महर्षि याज्ञवल्क्य के समय बनी, जिसमें वाचस्पति ने नव्य न्याय की धारणा जोड़ी। इसके मुताबिक दोष सिद्धि से पहले किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 कानून के समक्ष सबकी समानता और धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी किस्म के भेदभाव को निरस्त करता है। लेकिन यहां भारत सरकार ने जाति के आधार पर एक समूह को पहले ही अपराधी मान लिया है। किसी सभ्य समाज में ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी कैसे की जा सकती है?

इसी तरह का एक बिल मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी ले आई थी। कम्युनल वायलेंस बिल की मूल अवधारणा हिंदू को दंगाई मानने की थी। ऐसा कानून बन रहा था, जिसके मुताबिक कही भी दंगा होगा तो हिंदू को दोषी माना जाएगा। ठीक उसी तरह का नियम सरकार ले आई है, जिसके मुताबिक किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर भेदभाव होता है या उत्पीड़न की घटना होती है तो सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक को उसका दोषी माना जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग कभी भी आरोपी या दोषी नहीं बनाए जाएंगे।अब जरा इसके व्यावहारिक पक्ष की कल्पना करें। किसी भी शिक्षण संस्थान में जाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर कितना मानसिक दबाव होगा। वह हर समय इस आशंका में रहेगा कि उपरोक्त पांच समूहों का कोई छात्र उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है और उसका करियर समाप्त कर सकता है। क्या सरकार कथित ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा से दूर करना चाहती है?सरकार ने यह काम ऐसे समय में किया है, जब सामाजिक स्तर पर असमानता कम हो रही है, समाज ज्यादा समरस बन रहा है और सत्तारूढ़ दल खुद ही व्यापक हिंदू एकता के लिए काम कर रहा है। दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर असमानता बढ़ रही है। सरकार का यह नियम विभिन्न जातियों और समाजों के बीच वैमनस्य और भेदभाव बनाने वाला प्रतीत होता है।

अगर इसके राजनीतिक पहलुओं को देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार को लग रहा है कि वह सामान्य वर्ग को अलग थलग करके या उसके प्रति द्वेष दिखा कर एससी, एसटी और ओबीसी के बड़े जातीय समूह को अपने साथ करे लेगी और इससे उसे चुनावी जीत का स्थायी फॉर्मूला मिल जाएगा? क्या वह कांग्रेस और प्रादेशिक पार्टियों की बहुजन राजनीति के जवाब के तौर पर यह नियम लेकर आई है?

ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि भाजपा के नेता अर्थव्यस्था, कूटनीति, प्रौद्योगिकी आदि समझें न समझें राजनीति बखूबी समझते हैं। उनके पता होता है कि किस बात से चुनावी नुकसान होगा और किस बात से फायदा होगा। तभी हैरानी हो रही है कि राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला इतना बड़ा कदम इस सरकार ने कैसे उठाया।गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अल्पसंख्यकों को पहले ही अपने से अलग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में खुल कर 80 और 20 की लड़ाई बताई जाती है। लेकिन यह विभाजन राष्ट्रीय स्तर पर भी है। भाजपा ने 20 फीसदी अल्पसंख्यकों को अपने से अलग मान लिया है। उसे 80 फीसदी हिंदुओं की राजनीति करनी है। अब क्या वह इस 80 फीसदी के समूह को और छोटा करने की जोखिम ले सकती है? क्या इसमें से 15 फीसदी सामान्य वर्ग बाहर हो जाए तो भाजपा 65 फीसदी के वोट की राजनीति करके चुनाव जीत सकती है? ध्यान रहे सामाजिक स्तर पर एससी और एसटी का टकराव ओबीसी के साथ ज्यादा है।एससी, एसटी उत्पीड़न कानून के तहत 80 से 90 फीसदी मामलों में आरोपी पिछड़ी जातियों के हैं। इस कानून के दुरुपयोग के अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं और अदालतों ने इस पर अनेक बार टिप्पणियां की हैं। लेकिन शिक्षण संस्थान में ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ ही उत्पीड़न के शिकार वर्ग में शामिल किया जा रहा है। क्या इससे तीनों समूहों के बीच समाज में भी समरसता स्थापित हो जाएगी? इसमें संदेह है लेकिन इससे एससी, एसटी व ओबीसी के साथ सामान्य वर्ग के संबंधों में तनाव जरूर बढ़ जाएगा। क्या सरकार यह तनाव बढ़ाना चाहती है?अगर राज्यवार देखेंगे तो भाजपा को राजनीतिक नुकसान की संभावना और ज्यादा दिखेगी। मिसाल के तौर पर झारखंड में मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी भाजपा के खिलाफ हैं। अगर सामान्य वर्ग भी खिलाफ हुआ तो भाजपा के पास क्या बचेगा? उत्तर प्रदेश में 80 और 20 की लड़ाई है। 80 में से 10 फीसदी यादव को पहले ही भाजपा ने अलग कर दिया है। अगर बचे हुए 70 फीसदी में से 20 से 25 फीसदी सामान्य वर्ग के लोग अलग हुए तो भाजपा के पास क्या बचेगा राजनीति करने को?

भाजपा के नेता इतने नासमझ तो नहीं हैं कि वे यह मानने लगें कि शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी के साथ ओबीसी को भी शोषित वर्ग में शामिल कर देने से उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव भाजपा को वोट देने लगेंगे। दो तीन राज्यों के उदाहरण का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। सो, कुल मिला कर यूजीसी का यह नियम सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला और समानता की भावना के विपरीत तो है ही साथ ही भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि चौबे जी छब्बे जी बनने चलें और दुबे जी बन कर रह जाएं।

छत्तीसगढ़ मे आदिवासी नेतृत्व गढ़ रहा है विकास के नए सोपान

छगन लाल लोन्हारे

छत्तीसगढ़ की खूबसूरत वादियों में स्थित जशपुर जिला के ग्राम बगिया में 21 फरवरी को जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सज्जनता और सहृदयता की एक मिसाल है। दो वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ राज्य में विकास का एक नया आयाम गढ़ने वाले तथा प्रदेश के नागरिकों के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपनी लोकप्रियता के शिखर पर विद्यमान है। विष्णुदेव साय जनता के बीच के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनकी सदाशयता और दूरगामी योजनाओं से प्रदेश में विकास और प्रगति का राह आसान हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी पृष्ठभूमि से आते हैं।केबिनेट बैठक में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा

कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली त्यौहार से पहले एकमुश्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं एक किसान पुत्र हैं वे किसानों की पीड़ा को भलीभांति जानते हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से की की गई है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पूर्व किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी। किसान हितैशी सरकार के इस निर्णय से बाजार भी गुलजार होंगे, जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखाई देगा, ट्रैक्टर आदि की बिक्री में वृद्धि होगी।प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति से राज्य में अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दो साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक नई उंचाई पर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता का न केवल विश्वास जीता है बल्कि उनके हित को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिससे छत्तीसगढ़ का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। यह केवल और केवल विष्णुदेव साय जैसे एक संवेदनशील, कर्मठ तथा ऊर्जावान मुख्यमंत्री ही सम्भव कर सकते हैं। विष्णु देव की सुशासन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2026 को महतारी गौरव वर्ष घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रदेश के 42 हजार 878 महिला स्व- सहायता समूहों को आसान ऋण से अब तक 129.46 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को 237 करोड़ रूपए की सहायता राशि दी गई है। राज्य की 19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार सुनिश्चित की गई है। महिला सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई है। महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर 52.20 करोड़ की लागत से 179 महतारी सदनों का निर्माण कराया जा रहा है। महिला समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु 200 करोड़ की लागत से नवा रायपुर में यूनिटी मॉल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा आवास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख कर अब तक 26 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति किए गए हैं। स्वच्छ पेयजल सबका अधिकार है। प्रदेश के 41 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति के लिए राज्य में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं से प्रदेश के 3208 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के साथ रेल नेटवर्क मैप से बस्तर जुड़ रहा है। जगदलपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-विशाखापट्नम नई सड़क परियोजनाओं से विकास की नई राहें खुल रही है। प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण की पहल की जा रही है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना, कृषक उन्नति योजना, नियद नेल्ला नार, अखरा निर्माण योजना जैसी योजनाओं का शुभारम्भ किया है और जनता के बीच अपनी एक अलग छवि निर्मित की है।

टॉक्सिक के नए पोस्टर ने बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कन

यश, कियारा आडवाणी की टॉक्सिक, अपने दमदार टाइटल इंट्रो वीडियो के बाद से सबका ध्यान खींच रही है. फैंस इसके रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस इंतजार के बीच डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने फिल्म के टीजर का अनाउंस करके इस एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. यह फिल्म रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से क्लैश करेगी. हफ्तों के इंतजार के बाद, मेकर्स ने टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के टीजर रिलीज की तारीख का एलान किया है. गीतू मोहनदास ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यश का नया पोस्टर शेयर किया और टीजर रिलीज डेट बताते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, टॉक्सिक का टीजर 20.02.2026, सुबह 9:35. टॉक्सिक 19-03-2026 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में आएगी. पोस्टर में यश अपने किरदार में नजर आ रहे हैं. वह खून से लथपथ बर्फीली जमीन पर खड़े दिख रहे हैं. एक्टर बोतल से पानी पीते हुए दिख रहे हैं. मलबे और तबाही के बीच उनका चेहरा थोड़ा छिपा हुआ है. नया पोस्टर इस बात को और पक्का करता हैं कि फिल्म एक डार्क, स्टाइलिश एक्शन ड्रामा है जो एक हिंसक और नैतिक रूप से अस्पष्ट दुनिया में सेट है. फिल्म का टीजर आज 20 फरवरी को आएगा. टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स में कन्नड़ सुपरस्टार यश राया का रोल अदा करेंगे. कियारा आडवाणी नादिया की भूमिका में हैं, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रूप में नजर आएंगी. नयनतारा गंगा के रूप में हैं, जबकि तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत कलाकारों की टोली को पूरा करती हैं.

मंधाना की पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पटखनी देकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत

नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के दम पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना सकी और उन्हें मुकाबले में 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पहली बार कोई टी20 सीरीज जीती है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कोई द्विपक्षीय सीरीज में जीत हासिल की है। इससे पहले भारतीय टीम ने कभी भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीती थी। मंधाना की शानदार पारी फिर गेंदबाजी में श्री चरणी और श्रेयंका पाटिल की बेहतरनी गेंदबाजी के दम पर कौर की अगुवाई वाली टीम इतिहास रचने में कामयाब रही।

स्मृति मंधाना की शानदार बल्लेबाजी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना का बल्ला जमकर हल्ला बोला। भारत ने इस मुकाबले में 19 रनों के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था लेकिन मंधाना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक छोर को संभाले रखा और 55 गेंदों पर 82 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 8 चौके व 3 छक्के शामिल रहे। मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार खेल दिखाते हुए अर्धशतक लगाया। उन्होंने 56 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 56 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अर्धशतक के दम पर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाबेल सदरलैंड सबसे कामयाब गेंदबाज रहीं। उन्होंने 4 ओवर में 34 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ने एक-एक विकेट अपने नाम किए।

ऑस्ट्रेलिया की मुकाबले में हार

भारत के द्वारा दिए गए 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत अच्छी नहीं रही।

कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा... ओटीटी पर रिलीज

फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरीझ् 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी मेगा-बजट फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई थी. लेकिन समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो अपनी लव स्टोरी के लिए काफी चर्चा में रही है.

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरीझ् सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब डिजिटल के दर्शकों तक पहुंच चुकी है, जिससे वो घर बैठे इस हल्की-फुल्की प्रेम कहानी को देख सकते हैं. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है.

जो लोग सिनेमाघरों में ये फिल्म नहीं देख पाए थे, उनके लिए ये अच्छा मौका है. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरीझ् फिल्म 19 फरवरी यानी आज से ओटीटी प्लेट-फॉर्म अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है. स्ट्रीमिंग पार्टनर द्वारा फिल्म की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट की गई. इसके बाद इंटरनेट पर यूजर्स ने इसपर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है.

द केरल स्टोरी 2 को सेंसर बोर्ड ने किया पास, निर्माता विपुल शाह ने जताया आभार

फिल्म द केरल स्टोरी 2 : गोज बियॉन्ड का ट्रेलर जब से जारी किया गया है, यह विवादों में फंस गई है। हाल ही में, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने आलोचना करते हुए इसपर झूठा प्रचार करने क आरोप लगाया। इन विवादों के बीच, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दिखा दी है। सीबीएफसी ने प्रमाणपत्र के तहत 14 साल से ज्यादा उम्र के दर्शकों को फिल्म देखने की अनुमति दी है। द केरल स्टोरी 2 को अंडर ए प्रमाणपत्र देते हुए पास किया गया है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने बोर्ड के इस फैसले पर राहत और संतोष जताते हुए आभार व्यक्ति किया है। उन्होंने कहा, यह उस इरादे और ईमानदारी पर उनके विश्वास को दर्शाता है जिसके साथ हमने यह कहानी सुनाई है। यह फैसला विशेष रूप से अहम है, क्योंकि इससे हमें देशभर की युवा लड़कियों और परिवारों तक पहुंचने का मौका मिलता है।

अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को मिलेगा मौका?

नई दिल्ली। भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने उन लोगों के लिए चिंता जाहिर की है, जो अभिषेक के फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। सूर्या ने साफ किया कि उन्हें शर्मा पर पूरा भरोसा है और वे बाएं हाथ के बल्लेबाज के खराब प्रदर्शन से चिंतित नहीं हैं। अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं।शर्मा ने तीन मुकाबले खेले और तीनों मैचों में शून्य पर आउट हुए। ऐसे में उनको लेकर अब फैंस भी चिंतित हैं, जिसका जवाब अब कप्तान सूर्या ने दिया है। सूर्या का कहना है कि अभिषेक ने पूरे साल तक टीम के लिए अच्छा किया और अब हमारी बारी है। बता दें कि शर्मा को क्रिकेट के तमाम जानकार टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच विनर बता रहे थे लेकिन अभिषेक लगातार फ्लॉप रहे हैं और उनकी आलोचना भी हो रही है।

सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा पर दिया बयान

साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा, मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूं, जो अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने पूरे साल हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और अब उनकी कमी को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है।"

अभिषेक शर्मा के लगातार तीन डक

अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, विश्व कप में उनका बल्ला खामोश हो गया। उन्होंने यूएसए, पाकिस्तान और फिर नामीबिया के खिलाफ जीरो रन बनाए।

ऐसा खिलाड़ी, जिसे सबसे बड़ा मैच विनर माना जा रहा था, वो विश्व कप में अब तक खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रहा है। इसके बावजूद सूर्या ने अभिषेक का समर्थन किया है और उनके बयान से लग रहा है कि अभिषेक की जगह संजू सैमसन को मौका नहीं मिल पाएगा।

एक नजर

पुलिस व एसओजी ने पकड़ी डेढ़ किलो चरस

चमोली। पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त चेकिंग के दौरान दो लोगों को करीब डेढ़ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत डेढ़ लाख से अधिक बताई जा रही है। शुक्रवार देर शाम को ज्योतिर्मठ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम करछी रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दो संदिग्धों से पूछताछ कर उनकी तलाशी ली गई तो डेढ़ किलो चरस बरामद हुई। एसएसआई विनोद रावत ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में बीरबल फरस्वाण (20) निवासी ग्राम पाणा पोस्ट ईराणी के पास से 1100 ग्राम चरस और अजब सिंह (49) निवासी पाण पोस्ट ईराणी चमोली के पास से 550 ग्राम चरस बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत एक लाख 65 हजार रुपये आंकी जा रही है। अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने वाली टीम में एसएसआई विनोद रावत, एसआई एसओजी सत्येंद्र बुटोला, अपर उपनिरीक्षक भूपेंद्र, हेड कांस्टेबल किरणपाल, कांस्टेबल दिलबर सिंह, सलमान और रविकांत शामिल रहे।

मातृ भाषाएं और लोक भाषाओं के प्रयोग से ही बचेगा अस्तित्व

नई टिहरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पर राजकीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग की ओर से स्थानीय भाषा प्रकोष्ठ के बैनर तले स्थानीय बोली–भाषा पर परिचर्चा की गई। चर्चा में उपस्थित लोगों ने अपनी–अपनी स्थानीय भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. प्रणिता नंद ने कहा कि मातृ भाषाएं और लोक भाषाएं हमारी दैनिक दिनचर्या में जब प्रयोग होगी तब ही उस भाषा का अस्तित्व बचा रहेगा। अपनी दिनचर्या से हम अपनी मातृ भाषा को हटा देंगे तो वह विलुप्त हो जाएगी। स्थानीय भाषा प्रकोष्ठ के संयोजक और हिंदी विभाग के प्रभारी डॉ. जितेंद्र नौटियाल ने परिचर्चा की। इस मौके पर डॉ. विक्रम सिंह बर्त्वाल, डॉ. सुशील कुमार, डॉ. मनोज फोंदणी, डॉ. विजय प्रकाश भट्ट, अजय पुंडीर, आदित्य सिंह, छात्र संघ उपाध्यक्ष राहुल, प्रीति आदि मौजूद थे।

ट्यूबवेल पंप से गांव में पानी की समस्या का होगा समाधान

नई टिहरी। प्रतापनगर के ग्राम पंचायत आबकी में वर्षों से पेयजल समस्या बनी है। ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए विधायक विक्रम नेगी ने गांव में ट्यूबवेल पंप के लिए सात लाख रुपये की स्वीकृति करवाई है। आबकी गांव की जनसंख्या पांच सौ से अधिक है। गर्मियों में गांव के आसपास प्राकृतिक पेयजल स्रोतों पर पानी सूखने से ग्रामीणों के सामने पेयजल की संकट खड़ा हो जाता है। हालांकि गांव में जल जीवन मिशन के पेयजल लाइन बिछी है लेकिन गर्मियों में पेयजल स्रोतों पर पानी कम होने से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो पाती है। ग्रामीणों को कई किमी दूर से पानी ढोना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से शासन–प्रशासन से पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की मांग करते रहे हैं। पेयजल का स्थायी समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों को गर्मी में सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ग्रामीणों की मांग पर प्रतापनगर विधायक नेगी ने ट्यूबवेल के निर्माण के लिए सात लाख की धनराशि स्वीकृत करवाई है। उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल का निर्माण कार्य जल निगम के विद्युत नियंत्रण विभाग को दिया गया है। ट्यूबवेल निर्माण कार्य जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। गांव के नीचे सड़क पर लगने वाले ट्यूबवेल से आबकी गांव के लिए पानी की लिफ्टिंग की योजना है।

लाखों खर्च करने के बाद भी पार्क से गायब हुआ सुकून

सिद्धबली के समीप लाखों की लागत से किया गया पार्क का जीर्णोद्धार,पार्क में पड़े पत्थर व झाड़ियों की चपेट में आने से चोटिल हो रहे बच्चे

सिद्धबली मंदिर के समीप बदहाल पड़ा पार्क

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : वर्ष 2021 में कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग ने लाखों के बजट से सिद्धबली पार्क का जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन, देख-रेख के अभाव में आज यह पार्क बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। सुकून की तलाश में पार्क में प्रवेश कर रहे श्रद्धालुओं व पर्यटकों के बच्चे पत्थर व झाड़ियों की चपेट में आने से चोटिल हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह सब देखने के बाद भी विभाग मार्ग मरम्मत की सुध तक नहीं ले रहा।

दस लाख रुपये की लागत से विभाग ने पार्क का जीर्णोद्धार करवाते हुए झूले की मरम्मत, पार्क में गमले, टाइल्स बिछाने के साथ ही मनमोहक फूल व घास लगाई थी। निर्णय लिया गया था कि मंदिर के समीप स्थित इस पार्क को बेहतर तरीके से रखने के साथ ही समय-समय पर इसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। सौंदर्यीकरण तो हुआ नहीं लेकिन, जो पार्क कि स्थिति थी वह भी बिगड़ गई है। पार्क में लगाए गए अधिकांश झूले व अन्य सामान टूट चके हैं। शरारती तत्वों ने पार्क में गमलों को भी चोरी कर दिया है। पार्क के चारों ओर झाड़ियां उग चुकी हैं। कुछ दिन पूर्व झूला टूटने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल होते होते बच गया। शाम ढलते ही पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगा है। लोगों की शिकायत के बाद भी सरकारी सिस्टम व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

हैरिटैज एकेडमी की छात्राओं ने किया बेहतर प्रदर्शन

प्रतियोगिता में उपविजेता रही छात्राएं

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : हरिद्वार स्थित रोशनाबाद स्टेडियम में आयोजित नार्थ जोन अस्मिता रग्बी लीग प्रतियोगिता में हेरिटेज एकेडमी कोटद्वार की छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में छात्राओं को उपविजेता का खिताब मिला है।

प्रतियोगिता में कई टीमों ने प्रतिभाग किया। जिसमें कोटद्वार से एकेडमी की छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में अंडर-15 वर्ग में रिया कटारिया ने बेहतर पदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, अंडर-18 वर्ग में सृष्टि उपविजेता रही। टीम के कोच साहिल नेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर छात्राओं ने अकादमी का नाम रोशन किया है। कहा कि इससे पूर्व में विद्यार्थी कई प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

पौड़ी से फायर फाइटर अंकित ने जीते दो कांस्य पदक

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जनपद पौड़ी के फायर फाइटर अंकित ने ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट में दो कांस्य पदक जीते है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने अंकित को सम्मानित कर भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।

जयपुर राजस्थान में आयोजित ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट में जहां देशभर के प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। वहीं जनपद पौड़ी से प्रतिभाग करते हुए फायर फाइटर अंकित ने शानदार प्रदर्शन कर बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। साथ ही क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी टीम के साथ बेहतरीन समन्वय, अनुशासन एवं टीमवर्क का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रकार उन्होंने कुल 02 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जनपद का नाम गौरवान्वित किया। इस उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार द्वारा उन्हें सम्मानित कर बधाई दी गई और भविष्य में भी ऐसे ही उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया।

एग्रीस्टैक योजना के तहत आयोजित होंगे शिविर

जयन्त प्रतिनिधि। रूद्रप्रयाग : एग्रीस्टैक योजना के तहत स्थानीय कृषकों की सुविधा के लिए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं जिससे किसान कैंप में ही एग्रीस्टैक योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें। तहसीलदार ऊखीमठ रमेश चंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एग्रीस्टैक योजना हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षकों की तैनाती के लिए रोस्टर जारी किया गया है। जिसमें कृषि, उद्यान एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विकासखंड ऊखीमठ के न्याय पंचायत भवन मनसूना में राजस्व उप निरीक्षक गंभीर सिंह गुसांई वहीं कालीमठ जूनियर हाईस्कूल में राजस्व उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह, दैड़ा पंचायत भवन उषाणा, जयवीर सिंह राणा राजकीय प्राथमिक विद्यालय परकंडी, पंचायत घर जगोठ गणेशनगर, भटवाड़ी सुनार राजकीय इंटर कॉलेज कंडारा अजय नेगी इसके साथ ही बाड़व पंचायत घर चंद्रनगर, राजकीय इंटर कॉलेज फाटा में सुंदर लाल, गुप्तकाशी में कीर्ति राणा तथा पंचायत घर ल्वारा लमगोंडी में राजस्व उप निरीक्षक अमित पुंडीर को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी राजस्व उप निरीक्षकों को उनसे संबंधित क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं।

व्यवसायिक वाहनों के संचालन को खोला जाएं लालढांग-चिलरखाल मार्ग

विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : कांग्रेस ने लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग को एलिवेटेड बनाने के साथ ही इसे व्यवसायिक वाहनों के लिए भी खोलने की मांग की है। कहा कि जनता के लंबे संघर्ष के बाद न्यायालय ने मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी है। ऐसे में सरकार को इसके निर्माण के लिए गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। व्यवसायिक वाहनों के लिए मार्ग खुलने से ही क्षेत्र का बेहतर विकास होगा।

शनिवार को कांग्रेसियों ने जन समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। बताया कि 12 फरवरी को उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग निर्माण को स्वीकृति दी है। मार्ग निर्माण के लिए क्षेत्रीय जनता पिछले कई माह से संघर्ष कर रही थी। अब राज्य सरकार को चाहिए की मोटर मार्ग को एलेवेटेड बनाकर उस पर व्यावसायिक वाहनों के लिए भी खोला जाए। जिससे क्षेत्र के लोगों को मोटर मार्ग का लाभ मिल सके। कहा कि क्षेत्र की जनता विगत कई माह से मोटर मार्ग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद गेंद प्रदेश सरकार के पाले में है, प्रदेश सरकार को जनभावनाओं को अनुरूप एलेवेटिटेड रोड के लिए प्रक्रिया शुरू करवा देनी चाहिए। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिंटिंग जज से करवाए जाने की मांग की है। कहा कि अंकिता के माता-पिता ने मांग की थी कि हत्या की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अंकिता के माता-पिता के इच्छा के अनुरूप कार्यवाही करवाए जाने की मांग की है, जिससे हत्याकांड से जुड़े वीआईपी के नाम का शीघ्र खुलासा हो सके। इस मौके पर शंकेश्वर प्रसाद सेमवाल, बलबीर सिंह रावत, रमेश चंद्र खंतवाल, भारत सिंह नेगी, गोकुल सिंह नेगी, बीरेंद्र सिंह रावत, लक्ष्मी चौहान, शीला भारती, प्रेम सिंह पयाल, नरेंद्र सिंह नेगी, चंद्रमोहन सिंह रावत, योगेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप नेगी, कृपाल सिंह नेगी मौजूद रहे।

कोटद्वार तहसील में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते कांग्रेसी

स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाए ऊर्जा निगम

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : क्षेत्रवासियों ने ऊर्जा निगम से स्मार्ट मीटर को हटाकर नए मीटर लगाने की मांग की है। कहा कि स्मार्ट मीटर गरीब परिवारों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा है। ऐसे में इसके लिए सरकार को भी गंभीरता से कार्य करना चाहिए।

शनिवार को स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में धरना दिया। धरना देने वालों में आमपड़ाव, लकड़ीपडाव, ध्रुवपुर, कंभीचौड़, लालपानी सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल थे। लोगों ने कहा कि ऊर्जा निगम की ओर से जबरन उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इन स्मार्ट मीटरों में खपत से ज्यादा बिल आ रहा है, जबकि पुराने मीटरों में खपत के अनुसार ही बिल आ रहे थे, लेकिन विभाग ने जोर जबरदस्ती कर पुराने मीटरों को उखाड़ कर उनके स्थान पर स्मार्ट मीटर लगा दिए। कहा कि जिन घरों में पुराने मीटरों को उखाड़ कर स्मार्ट मीटर लगाए गए है, उन्हें हटाकर पुरानी व्यवस्था को बनाया जाए। इस मौके पर महेश नेगी, आशाराम, रंजना रावत, बलवीर सिंह रावत, परमानंद, मदन सिंह, सुशील चौधरी, शोभा देवी, मीनाक्षी देवी मौजूद रहे।

कोटद्वार तहसील परिसर में स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना देते क्षेत्रवासी।

कुलिंग ग्राम पंचायत में तैनात हो प्रशासक, एसडीएम को भेजा पत्र

चमोली। विस्थपित ग्राम पंचायत कुलिंग के निवर्तमान ग्राम प्रधान ने एसडीएम को पत्र लिखकर गांव में प्रशासक की तैनाती की मांग की। वर्ष 2018 की आपदा से प्रभावित कुलिंग ग्राम पंचायत के 65 परिवारों को करीब छह किमी दूर दीदना तोक में विस्थापित किया गया था लेकिन दीदना में सड़क व स्कूल की सुविधा नहीं दी। 2008– 09 में नौ किमी सड़क को अब तक सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं मिली। कुलिंग के ग्रामीणों ने दीदना गांव में सड़क जाने के बाद ही गांव की सरकार बनाने के निर्णय के तहत पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया था। ऐसे में यहां ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाया। अब निवर्तमान ग्राम प्रधान हुकम सिंह बिष्ट ने एसडीएम को भेजे पत्र में बताया कि प्रशासनिक सहित कार्य के संपादन के लिए प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है। उन्होंने शीघ्र प्रशासक की तैनाती की मांग की। वहीं इस बारे में बीडीओ जयदीप बैरवाण ने बताया कि प्रशासक की तैनाती डीपीआरओ के स्तर से होनी है। इस बारे में जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

देवभूमि में बढ़ता अपराध चिंता का विषय

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री डा. हरक सिंह रावत ने कहा कि देव भूमि में बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। राजधानी में पिछले 20 दिन से पांच से अधिक हत्याएं हो चुकी है। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्थाओं से आमजन के मन में खौफ बना हुआ है।

कल्जीखाल क्षेत्र के अंतर्गत भेटी में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व काबीना मंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे। लेकिन, चुनाव जीतने के बाद भाजपा के नेता अपना वादा भूलकर जनता का शोषण करने में जुटे हुए हैं। प्रदेशवासी स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता था। आज वह अपराध की भूमि बनती जा रही है। राजधानी देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था कई सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। कहा कि अग्निवीर योजना बेरोजगारों के साथ धोखा है। कहा कि कांग्रेस जनता के हितों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता सुंदरलाल मुयाल, सेवानिवृत्त कर्नल रामरतन सिंह नेगी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष कल्जीखाल सुधीर सिंह, रणवीर लाल, यशोदा देवी आदि मौजूद रहे।

गढ़वाली भाषण प्रतियोगिता में पल्लवी, काव्य पाठ में लक्ष्मी प्रथम

चमोली। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस को गढ़वाली भाषा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। अंग्रेजी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं की भाषण, काव्यपाठ, औखांण सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में पल्लवी प्रथम,कार्तिक द्वितीय और दिया तृतीय स्थान पर रहीं। गढ़वाली काव्य पाठ में लक्ष्मी प्रथम, कार्तिक द्वितीय और जसवंत तृतीय स्थान पर रहे। वहीं, औखांण प्रतियोगिता में जसवंत प्रथम स्थान पर रहे। गढ़वाली लोक गीत में अपेक्षा प्रथम, उमा द्वितीय और जसवंत तृतीय रहे। लोक नृत्य में गायत्री प्रथम, अपेक्षा द्वितीय और आरती तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एमपी नगवाल ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में स्थानीय भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। गढ़वाली एक समृद्ध भाषा है, दैनिक व्यवहार में अधिक से अधिक उपयोग कर हम इसे अगली पीढ़ी के लिए संरक्षित रख सकते हैं। विशिष्ट अतिथि लोक गायक धनपत शाह ने स्वरचित कविताओं और गीतों से मातृभाषा को संरक्षित करने का आह्वान किया।

बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए दो सचल दल गठित

चमोली। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए पोखरी ब्लॉक में दो सचल दल गठित कए गए हैं। जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों में औचक निरीक्षण करेंगे। खंड शिक्षाधिकारी विनोद मटूड़ा ने बताया कि पोखरी ब्लॉक में कला विषय के विद्यार्थी न होने से जीआईसी गोदली, जीआईसी उड़ामांडा, जीआईसी पोगठा, जीआईसी थालाबैंड, जीआईसी देवीखेत, जीजीआईसी पोखरी, जीआईसी चौड़ी और जीआईसी सरमोला में 23 फरवरी को छात्र–छात्राएं पहली परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक निर्धारित है। सभी केंद्रों पर पुलिस तैनात रहेगी, इसके अलावा दो सचल दल गठित किए गए हैं, एक दल का वह स्वंय नेतृत्व करेंगे, दूसरे दल का नेतृत्व उप शिक्षा अधिकारी नेहा भट्ट करेंगी। ब्लॉक के आठ परीक्षा केंद्रों में दसवी के 374 और इंटर के 327 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

स्वच्छ भारत निर्माण के लिए सफाई पर दें ध्यान

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : भारत सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल की ओर से मैंदनी गांव में एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में शनिवार को स्वयं सेवियों ने सफाई अभियान चलाते हुए ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया।

आयोजित शिविर के चौथे दिन प्राध्यापक डा. विपिन पवार व कार्यक्रम अधिकारी डा. भारती ने विद्यार्थियों को स्वच्छता के बारे में बताया। कहा कि स्वच्छता केवल सफाई का नाम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जहां स्वच्छता होती है। वहां स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि स्वयं आती है। गंदगी न केवल बीमारियों को जन्म देती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और समाज की छवी को भी खराब करती है। इसके उपरांत विद्यार्थियों को गांव के आसपास फैली गंदगी को एकजगह एकत्रित कर उसे नष्ट किया। साथ ही ग्रामीणों से कूड़े को केवल कूड़ेदान में डालने की अपील की गई। कहा कि गांव को स्वच्छ बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मौके पर डा. कमल आर्य आदि मौजूद रहे।

मैंदनी गांव में स्वच्छता अभियान चलाते स्वयं सेवी

छः दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हुआ समापन

जयन्त प्रतिनिधि।

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलाप केंद्र में एमएमटीटीसी के तत्वावधान में पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परम्परा का एकीकरण विषय पर छः दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में 95 शिक्षक और शोधार्थियों प्रतिभाग किया, जिन्हें कार्यक्रम के समापन पर प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

समापन समारोह का मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. पवन सिन्हा और कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर एमएमटीटीसी के निदेशक प्रो देवेंद्र सिंह नेगी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरूजी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट किया। मुख्य अतिथि प्रो. पवन सिन्हा ने अपने संबोधन में भारतीय ज्ञान परम्परा की प्रासंगिकता को समकालीन परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता सस्टेनेबिलिटी और क्षमता निर्माण का वास्तविक आधार हमारी स्वदेशी ज्ञान परंपरा में निहित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि स्वदेशी तकनीक जैसे क्रायोजेनिक तकनीक ने न केवल भारत को वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि वैश्विक स्तर पर सम्मान भी दिलाया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी चुनौतियों से निपटने में भी देशी अनुसंधान और तकनीकी क्षमता निर्णायक सिद्ध हुई। भारतीय ज्ञान परंपरा पुनः उपयोग पर्यावरण संतुलन और जीवन के समग्र विकास की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना नहीं, बल्कि चरित्र, विवेक और राष्ट्रीय चेतना का निर्माण होना चाहिए। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक दृष्टि को सुदृढ़ करते हैं तथा पारंपरिक ज्ञान और समकालीन चिंतन के बीच सार्थक संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि आज अकादमिक शोध के प्राचीन भारतीय परिपेक्ष्य को समझने की जरूरत है। इस अवसर पर संकायाध्यक्ष प्रो. मोहन सिंह पंवार, चौरास परिसर निदेशक प्रो. राजेंद्र सिंह नेगी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. ओपी गुसाईं, डॉ. अमरजीत परिहार, यूजीसी के पर्यवेक्षक प्रो. आरएल नारायण सिम्हा, डॉ. राहुल कुंवर आदि मौजूद थे।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की तरफ से, उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद निम्नलिखित कार्य के लिए दो पैकेट प्रणाली के तहत खुली ई–निविदा आमंत्रित करते हैं।

1	कार्य का नाम व स्थान	उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के कार्य क्षेत्र में मुरादाबाद में 60 बिस्तरों वाले नए पुरुष बैरक का निर्माण, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों के लिए शौचालय, मैस, स्टोर, जिम, भोजन कक्ष और मनोरंजन कक्ष सहित 2 कमरे डी, मुरादाबाद–काशीपुर सेक्शन पर किलोमीटर 1391/317 (मुख्य लाइन) से 7/480 (काशीपुर लाइन) तक अतरसोली की चारदीवारी का निर्माण कार्य, मुरादाबाद चंदौसी सेक्शन पर विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए चौड़ी चारदीवारी का निर्माण कार्य, जंग बहादुर गंज स्टेशन पर माल गोदाम के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण सहित एक पूर्ण रेक माल ढुलाई लाइन का निर्माण, रोजा स्टेशन पर माल गोदाम और माल लाइन संख्या 5 और 6 के प्रस्तावित विस्तार का कार्य या किसी अन्य स्थान/स्टेशन पर कोई अन्य कार्य करने के संबंध में।
2	कार्य पूरा करने की अवधि	12 (बारह) माह
3	कार्य की अनुमानित लागत	रू. 3584.97 लाख
4	जमा की जाने वाली जमानत राशि	रू. 19,42,500.00
5	निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र की वृहत जानकारी	ई निविदा प्रपत्र की वृहत सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। उपर्युक्त निविदा प्रपत्र आईआरईपीएस की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर दिनांक 21.02.2026 से दिनांक 18.03.2026 को 15:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। उपर्युक्त टेण्डर के सम्बन्ध में अन्य सभी नियम व शर्तें टेण्डर डॉक्यूमेंट में दी गई है। निविदा सूचना की वृहत जानकारी कार्यालय में निविदा सूचना बोर्ड से की जा सकती है।
6	अन्तिम तिथि/ ई–निविदा अपलोड करने की तिथि	18.03.2026 को 15:00 बजे तक। ई–निविदा दिनांक 02.03.2026 से 18.03.2026 को 15:00 बजे तक आईआरईपीएस की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।
7	ई–निविदा खुलने की तिथि व समय	टेक्निकल कम कमर्शियल बिड दिनांक 18.03.2026 को 15:00 बजे तक ई–टेण्डर अपलोडिंग बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जाएगी। योग्य टेंडरर की फाइनेंशियल बिड कार्यालय द्वारा दी गई दिनांक व समय की सूचना के आधार पर बाद में खोली जाएगी।

निविदा सूचना सं. डब्लू टेण्डर 295/उप मु.अभि. नि. मुरादाबाद — दिनांक 21.02.2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ — 599/2026

संक्षिप्त समाचार

डीपीआर के विपरीत बिछाई कार्यदायी संस्था ने पेयजल लाइन, ग्रामीणों में रोष

उत्तरकाशी। जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से निर्मित थुनाराडामटी पेयजल योजना पर ईशाली गांव के ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि योजना की डीपीआर में चयनित मूल स्रोत सिशोना तोक से लाइन बिछाने के बजाय कार्यदायी संस्था ने गांव से करीब तीन किमी दूर खनवाटा तोक गदेरे के पारंपरिक स्रोत से पाइप लाइन जोड़ दी है। गांव की पूर्व उप प्रधान रोहिला देवी, रंगिता, प्रीति राणा आदि ने बताया कि डीपीआर में स्पष्ट उल्लेख था कि ईशाली गांव के 145 परिवारों के लिए लगभग आठ किमी दूर स्थित सिशोना तोक के स्रोत से पेयजल लाइन बिछाई जानी थी लेकिन ठेकेदार की ओर से गदेरे के बीचों–बीच पाइप लाइन डाल दी गई है। इससे बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से पाइप लाइन बार–बार क्षतिग्रस्त होती है जिससे गांव में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। साथ ही गदेरे के पारंपरिक स्रोत से छेड़छाड़ कर भविष्य में गंभीर जल संकट का कारण बन सकती है। वहीं, गांव की चुन्ना देवी, सुभद्रा राणा, मंजू राणा, नीना राणा, रजनीश राणा, रमेश राणा तथा ग्राम प्रधान सुजीत सिंह राणा ने कहा कि यदि डीपीआर में चयनित स्रोत से ही लाइन नहीं बिछाई गई तो ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं बनी सहमति, दो के नाम भेजे पैनल में

चमोली। शनिवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की संगठन सृजन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बनने से दो दावेदारों के नामों का पैनल हाईकमान को भेजा गया। पार्टी के संगठन सृजन के पर्यवेक्षक लक्ष्मण रावत, विधान सभा प्रभारी हरीश चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष के लिए वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत, संजय नेगी और नीरज पुरोहित ने दावेदारी की। रायशुमारी के बाद नीरज पुरोहित ने नाम वापस ले लिया। लेकिन किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। जिसके चलते पार्टी हाईकमान के लिए पैनल में नाम भेज दिए गए हैं। विधानसभा प्रभारी हरीश चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी है। महिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश असुरक्षित है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकार की गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाना होगा। बैठक में ब्लॉक महिला अध्यक्ष ऊषा रावत, जिला महा मंत्री जन संपर्क संदीप कुमार पटवाल, विजेंद्र रावत, देवेंद्र रावत, चंद्र सिंह नेगी, सुदर्शन रावत, मनमोहन नेगी आदि मौजूद थे।

नंदाकिनी क्लस्टर नंदानगर करेगी कौणी का उत्पादन, निजी फर्म के साथ हुआ एमओयू

चमोली। ग्राम उत्थान परियोजना (रीप) के अंतर्गत आने वाली नंदाकिनी क्लस्टर नंदानगर की महिलाएं कौणी का उत्पादन करेंगी। इसे एक निजी फर्म खरीदेगी। फर्म ने नंदाकिनी क्लस्टर के साथ एमओयू किया है। फर्म पहले नंदाकिनी क्लस्टर से कौणी के बीज खरीदेगी। खरीदे बीजों को वे उन्हीं क्लस्टर को उत्पादन के लिए देंगे। उत्पादन होने के बाद उसी कौणी को खरीदा भी जाएगा।

इससे 250 से अधिक महिलाओं को घर बैठे की अच्छा रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिकी मजबूत होगी। महिलाओं को स्थानीय स्तर पर आसानी से रोजगार मिल जाए। इसके लिए रीप की ओर से विभिन्न निजी कंपनियों से लगातार वार्ता की जा रही है। चमोली जनपद के नंदानगर के नंदाकिनी क्लस्टर के साथ एक निजी फर्म ने एमओयू किया है।

दो दिवसीय सेमीनार का हुआ समापन, 60 से अधिक शोध पत्रों का हुआ वाचन

चमोली। डॉ. शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से आयोजित दो दिवसीय सेमीनार शनिवार को संपन्न हो गया है। सेमीनार में देश के विभिन्न क्षेत्रों के 60 शोधार्थियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अपने शोध पत्रों का वाचन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. शिक्षा सेमवाल ने कहा कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत हर दृष्टि से आत्मनिर्भर था। उन्होंने कहा कि सतत विकास के माध्यम से ही आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ सकता है। प्राचार्य प्रो. राम अवतार सिंह ने कहा कि दो दिवसीय संगोष्ठी के में शोधार्थियों की ओर से उल्लिखित शोध पत्र आत्मनिर्भर भारत के विकास की नींव का पत्थर साबित होगा।

सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के भाई सीमा के प्रहरी : धामी

जनजाति समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली के बिरही (बेड़ूबगड़) में नीति-माणा जनजाति कल्याण समिति चमोली की ओर से आयोजित तीन दिवसीय हिउजनजाति समागम 2026के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये कार्यक्रम हमारी जनजातीय परंपराएं, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। जनजातीय समाज ने सदियों से अपनी परंपराओं और प्रकृति संरक्षण की भावना को पहचान दिलाने का काम किया है। कहा कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय भाई देश के सजग प्रहरी भी हैं। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भोटिया समुदाय की नीति माणा की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए आवंटित होने वाले बजट को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है। आज जनजातीय समुदाय को बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है, वहीं विपक्ष ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक समझा। लेकिन उन्होंने कभी भी जनजातीय समाज को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान नहीं किए। मुख्यमंत्री ने आयोजन में जनसहभागिता को अनुपम उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन ही उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान हैं। ये आयोजन न केवल समाज में समरसता और एकता को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल जड़ों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय ने सदियों से अपनी परंपराओं, लोकज्ञान और प्रकृति-संरक्षण की भावना से हमारी सभ्यता को मजबूती प्रदान की है। विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जनजातीय भाई-बहनों का जीवन हमेशा से संघर्ष, अनुशासन और सामूहिकता की अनुपम मिसाल रहा है। आज आवश्यकता है कि हमारी इस महान जनजातीय परंपरा के पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय उत्पादों और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजा जाए, जिससे ये ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। इस मौके पर थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली दौलत सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, नगर पालिका अध्यक्ष गोपेश्वर संदीप रावत, नीति माणा जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष हरीश परमार, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार बीडी सिंह, दलबीर दानू, राज्य मंत्री हरक सिंह नेगी, बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, चंद्रकला तिवारी, नंदी राणा, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने की यह घोषणाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति घाटी भोटिया जनजाति के शीतकालीन प्रवास एवं अन्य भूमि संबंधी मामलों का निस्तारण करने, बेड़ू बगड़ भोटिया पड़ाव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने, स्व. श्रीमती गौरा देवी जी की प्रतिमा एवं पार्क निर्माण कराने, बैरासकुंड मंदिर का सौंदर्यीकरण करने, बेड़ू बगड़ पड़ाव की भूमि को सुरक्षित करने के लिए कार्य कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी घोषणाओं का परीक्षण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

लोकार्पण के दो महीने बाद ही उखड़ी विकास की परत

– 468 .89 करोड़ की लागत से किया गया था सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य

उत्तरकाशी। खाटल पट्टी की लाइफ लाइन गढ़ आंबेडकर मोटर मार्ग का डामरीकरण लोकार्पण के महज दो माह बाद ही उखड़ गया। इससे मोटर मार्ग की गुणवत्ता पर सवाल उठा कर स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मोटर मार्ग का पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दिसंबर में लोकार्पण किया था। साथ ही इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया था। राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों की ओर से विधायक को सम्मानित भी किया। मार्ग की घटिया गुणवत्ता की पोल महज दो माह में ही खुल गई। पांच किमी लंबे गढ़ आंबेडकर मोटर मार्ग पर लोनिवि बड़कोट ने 468.89 करोड़ की लागत खर्च कर सुधारीकरण एवं डामरीकरण करवाया था जिसका डामर उखड़ना शुरू हो गया। मोटर मार्ग पर लोग जोखिम भरी आवाजाही कर रहे हैं। खाटल पट्टी के गढ़, मण्डा, देवल, चोपड़ा, कसलना, न्यूड़ी, गांव के लोग बड़ी मात्रा में टमाटर, मटर, आलू, फ्रेंचबीन और सेब की फसल का उत्पादन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सोबत सिंह राणा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने मोटर मार्ग की गुणवत्ता पर कई बार सवाल उठाए हैं लेकिन विभाग ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। मोटर मार्ग हमारे क्षेत्र की लाइफ लाइन है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जांच न होने पर आंदोलन किया जाएगा। एक साथ सुधारीकरण और डामरीकरण कार्य करने पर कुछ समय तक इस तरह की दिक्कतें आती हैं। गुणवत्ता में किसी भी तरह कमी नहीं है। जहां डामरीकरण उखड़ा है मौसम अनुकूल होते ही दुबारा करवा दिया जाएगा। – तनुज काम्बोज, अधिशासी अभियंता लोनिवि बड़कोट।

नौकरी के नाम पर बेरोजगार युवकों से 2.10 लाख की ठगी

नई टिहरी। टीएचडीसी के अधीन कार्य कर रही निटकॉन कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर 2.10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बेरोजगार युवकों ने पुलिस को दी तहरीर में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पिपोला निवासी अंकित कंडवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि वह रुद्रपुर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। इस दौरान उसके चाचा कैलाश चंद ने बताया कि गोविंद रतूड़ी नाम का एक व्यक्ति खुद को टीएचडीसी में कार्यरत बताता था। वह कुछ पैसे लेकर नौकरी लगा रहा है। उन्होंने खुद भी उस व्यक्ति को नौकरी लगाने के लिए 30 हजार रुपये दिए हैं। पीड़ित ने बताया कि उसके भाई अमित कंडवाल भी आरोपी गोविंद से अगस्त 2025 में मिला था। तब उसने टीएचडीसी के अधीन कार्य कर रही कंपनी निटकॉन में नौकरी लगाने का आश्वासन दिया था। नौकरी लगाने के बदले उसने हमसे 60 हजार रुपये मांगे। पीड़ित ने कहा कि नौकरी लगने के लालच में दोनों भाइयों ने आरोपी को अलग–अलग तिथियों में गूगल पे कर 60 हजार रुपये दे दिए। पैसे लेने के बाद आरोपी गोविंद ने निटकॉन कंपनी में नौकरी लगाने का नियुक्ति पत्र दे दिया और छह नवंबर को आने को कहा। हम दोनों भाई नवंबर में उससे मिलने गए तो वह टालमटोल करने लगा।

कई दिनों बाद पता चला कि गोविंद रतूड़ी फ्रॉड व्यक्ति है। जानकारी मिली कि उसने हम दोनों भाइयों के अलावा नौकरी लगाने के नाम पर पिपोला गांव के छह–सात लोगों से करीब 2.10 लाख रुपये लिए हैं।

सेवा टीएचडीसी के सहयोग से सिलाई प्रशिक्षण संपन्न

नई टिहरी। सेवा टीएचडीसी के वित्तीय सहयोग से भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनीसैण की ओर से लामरीधार में संचालित चार माह का सिलाई प्रशिक्षण समापन हो गया। प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। जाखणीधार ब्लॉक के लामरीधार में सेवा टीएचडीसी के सहयोग से गत अक्टूबर में 2025 में शुरू हुए चार माह के सिलाई प्रशिक्षण का जिला पंचायत सदस्य गीता देवी और टीएचडीसी के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह राणा ने समापन किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के जेलम, खंडोगी, अंद्रेठी, रतोली आदि गांव की 35 महिलाओं ने चार माह तक सिलाई प्रशिक्षण लिया। समापन पर सभी को प्रशिक्षण पत्र भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सचिव ज्ञान सिंह रावत, कुलदीप कैंतुरा, सीताराम थपलियाल, विक्रम उनाल आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की 257 करोड की वित्तीय स्वीकृति

कोटद्वार में विकास कार्यों के लिए 285 .64 लाख स्वीकृत

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सड़क सुधारीकरण कार्यों के साथ ही विभिन्न स्थानीय निकायों के तहत किये जाने वाले विकास कार्यों, जल उपचार संयत्रों की स्थापना, ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक निर्माण आदि के लिये कुल 257 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कोटद्वार में ऑटोमेटेड डाईविंग टेस्ट ट्रैक निर्माण परियोजना हेतु संस्तुत धनराशि 246.60 लाख के सापेक्ष 79.68 लाख अवमुक्त किये जाने के साथ ही लघु सिंचाई विभागान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु नवीन एसएलएस हेतु 39.04 लाख राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत मोरनौला जैती मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 4.26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र भीमताल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर कोठगोदाम बाईपास मोटर रोड (काठगोदाम से रानीबाग खंड) के निर्माण हेतु 4.70 करोड, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौडी के विकासखण्ड कोट में व्यासघाट से ग्राम सिल्सू मोटर मार्ग के किमी. 1.00 से किमी. 5.00 में पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 3.86 करोड, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून-किमाड़ी-लम्बीधार-कार्ट मेकेन्जी कम्पनी गार्डन मोटर मार्ग के किमी 1 से 24 (सप्लाई कैल्ट से लम्बीधार, बासागाढ़ मसूरी तक सिंगल लेन से इण्टरमीडिएट लेन में परिवर्तन हेतु अतिरिक्त पहाड़ कटान क्रॉस ड्रेन एवं दीवारों का निर्माण हेतु 14.55 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री ने 15वें वित आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त शहरी स्थानीय निकायों को आबद्ध अनुदान/निर्दिष्ट अनुदान के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय किश्त हेतु 58.37 करोड़, शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत 08 नगर निकायों, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम, नगरपालिका परिषद गौचर, नगर पंचायत महुवाखेड़ागंज, नगर पंचायत चमियाला, नगरपालिका परिषद किच्छा, नगर पंचायत नन्दप्रयाग, नगरपालिका परिषद नरेन्द्रनगर एवं नगर पंचायत तपोवन में 'देवभूमि रजत जयंती पार्क' के निर्माण हेतु 5.65 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चतुर्थ त्रैमासिक किश्त 79.09 करोड़ के साथ ही 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र हेतु 81.57 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

शिविर में ग्रामीणों ने करवाई आंखों की जांच

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : ग्राम सरूड़ा हनुमंती में ग्रामीणों के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 25 फरवरी को कोटद्वार आने को कहा गया।

शनिवार को देवभूमि नेत्र चिकित्सालय के डा. अरूण नेगी की आओ से शिविर का आयोजन किया गया। शिवर में दूर-दूर से ग्रामीण पहुंचे हुए थे। शिविर में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ग्रामीणों ने अपनी आंखों की जांच करवाई। साथ ही चिकित्सकों ने ग्रामीणों को आंखों की बेहतर सुरक्षा के टिप्स दिए। कहा कि आंखों से ही हम पूरे संसार को देखते हैं। ऐसे में आंखे हमारी जीवन की सबसे अनमोल चीज है। हमें समय-समय पर आंखों की जांच करवानी चाहिए। शिविर में ग्रामीणों की आंखों में मोतियाबिंद की भी जांच की गई। कहा कि 25 फरवरी को कोटद्वार में मोतियाबिंद का निःशुल्क आपरेशन किया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान सरुड़ा हनुमंती पुष्पा देवी, जिलाध्यक्ष क्रांति दल मुकेश बड़थ्वाल, राजेंद्र वेदवाल बबीता, सारिका, निकता आदि मौजूद रहे।

देहरादून में प्रदेश के पहले 'आंचल कैफे प्लस' का शुभारंभ

देहरादून। रायपुर रोड स्थित दुग्ध संघ देहरादून परिसर में प्रदेश के पहले 'आंचल कैफे प्लस' शुरू हो गया। इसका शुभारंभ काबीना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि उपभोक्ताओं को आंचल दूध और उससे निर्मित उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कैफे की स्थापना की गई है । उन्होंने इसे विभाग का सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि इससे आंचल ब्रांड को नई पहचान मिलेगी और भविष्य में अन्य जनपदों में भी ऐसे कैफे खोले जाएंगे। कैफे के संचालन के लिए तरूण एन्टरप्राईजेज कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है। कहा कि यह पहल रोजगार सृजन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यहां 20 लोगों को रोजगार दिया गया है, जिनमें 80 प्रतिशत स्थानीय नागरिक हैं ।

अल्मोड़ा अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक जल्द शुरू करेगा मोबाइल बैंकिंग सेवा

अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जल्द ही अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू करने जा रहा है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.सी. तिवारी ने बताया कि इस संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बैंक के ग्राहकों का आभार जताते हुए कहा कि उनके निरंतर विश्वास और सहयोग से ही बैंक नई सुविधाएं शुरू करने में सफल हो रहा है। बैंक अध्यक्ष महेश चन्द्र जोशी ने कहा कि बैंक अनुभवी नेतृत्व और प्रबंधन के निर्देशन में लगातार प्रगति कर रहा है और ग्राहक हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उपाध्यक्ष डॉ. वसुधा पंत ने बताया कि वर्तमान में बैंक की 65 शाखाएं संचालित हैं और कुल कारोबार करीब 6000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। बैंक का नेट एनपीए शून्य है और करीब 45 लाख खाताधारक इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि बैंक उत्तराखंड के शीर्ष आयकरदाताओं में भी शामिल है। बैंक ने वर्ष 2028 तक 100 शाखाएं स्थापित करने, 8000 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल करने और प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये सकल लाभ अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

तीन साल पहले आपदा में टूटा भवन, मुआवजे के लिए भटक रहा परिवार

चमोली। तीन साल पहले बरसात में पीएम आवास योजना से निर्माणाधीन भवन ध्वस्त हो गया था। इसके बाद से पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए भटक रहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। गोपेश्वर के पाडुली गांव निवासी सुरेश लाल ने बताया कि उनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर स्वीकृत हुआ था। उन्हें प्रथम किश्त के तौर पर एक लाख 80 हजार रुपये मिले जिससे उन्होंने भवन निर्माण करवाया लेकिन 2022 में निर्माणाधीन भवन आपदा में ध्वस्त हो गया। उन्होंने कर्ज लेकर फिर निर्माण शुरू किया लेकिन 2024 की बरसात में बोल्डर आने से मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। वे शुरू से मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार वर्तमान समय में ब्रह्मसैंण में किराये पर निवास कर रहा है। सुरेश लाल ने बताया कि वह मजदूरी करता है, जिसमें मकान का किराया चुकाना और परिवार को पालना संभव नहीं हो पा रहा है। कई महीनों का किराया बकाया चल रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें अन्यत्र विस्थापित कराया जाए, जिससे परिवार को स्थाई छत मिल सके। उनका कहना है कि प्रशासन ने शुरू में मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

दून में 1 मार्च को निकलेगी 'वादा याद दिलाओ' पद यात्रा

देहरादून। न्यू कैंट रोड क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरोध में 'पर्यावरण बचाओ आंदोलन' के तहत स्थानीय नागरिकों की ओर से मुख्य पद यात्रा 1 मार्च को निकाली जाएगी।

इस पद यात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके उस आश्वासन की याद दिलाना है, जिसमें उन्होंने सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ न काटने के लिए जीओ जारी करने की बात कही थी।

यह पद यात्रा सुबह 8:30 बजे देहरादून के दिलाराम चौक (राष्ट्रीय ध्वज स्थल) से शुरू होकर सैंटरियो मॉल तक निकाली जाएगी। इसमें स्थानीय निवासी, व्यापारी और पर्यावरण प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने 234 .55 करोड़ की लागत से 34 महत्वपूर्ण कार्यों का किया शिलान्यास

जयन्त प्रतिनिधि।

हरिद्वार : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेला हरिद्वार के दिव्य एवं भव्य आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए 234.55 करोड़ की लागत से 34 प्रमुख अवसंरचना कार्यों का शिलान्यास किया गया। कुंभ मेला नियंत्रण भवन में शनिवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप कुंभ मेला-2027 के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन के साथ-साथ हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास को सुदृढ़ करने में यह अवस्थापना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने घाट निर्माण एवं सिंचाई अवसंरचना (सिंचाई विभाग) कुल 07 कार्य लागत 70.54 करोड़, अपर गंगा नहर के दाएं एवं बाएं तट पर विभिन्न स्थानों पर घाटों का निर्माण एवं पुनर्विकास, 90 मीटर स्पान का कम्पोजिट स्टील गर्डर द्वि-लेन सेतु निर्माण, 03 अस्थायी पुलों की स्थापना, मरम्मत एवं रख-रखाव, सड़क एवं परिवहन अवसंरचना (लोक निर्माण विभाग) कुल 12 कार्य लागत 127.23 करोड़, बहादराबाद-सिडकुल चार लेन मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग-334 (दिल्ली-हरिद्वार-देहरादून) का चौड़ीकरण, नगर क्षेत्र में बीसी (बिटुमिनस कंक्रीट) द्वारा नवीनीकरण, फुटपाथ निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, प्रशासनिक रोड कॉरिडोर का विकास, पेयजल एवं जल आपूर्ति अवसंरचना (जल संस्थान) कुल 09 कार्य लागत 18.11 करोड, पंपिंग जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्गठन, 1500 केएल क्षमता का ओवरहेड टैंक एवं ट्यूबवेल निर्माण, 10 मीटर व्यास के 05 आरसीसी इन्फिल्ट्रेशन कुओं का निर्माण, श्रद्धालु सुविधाएं एवं सहायक अवसंरचना कुल 06 कार्य लागत 18.67 करोड़, चंडी देवी एवं मनसा देवी मंदिर मार्ग पर तीर्थयात्रियों हेतु सुविधाओं का विकास, बैरक एवं औषधि भंडारण कक्ष का निर्माण, मेला नियंत्रण भवन का नवीनीकरण एवं अतिरिक्त बैरकों का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला, शिक्षा निदेशालय में मचा हड़कंप

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर में घुसकर भाजपा विधायक और उनके समर्थकों द्वारा अफसर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊअपने समर्थकों के साथ शिक्षा निदेश-ाक अजय कुमार नौडियाल के दफ्तर पहुंचे और विवाद के बाद मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट में अफसर के सिर पर गहरी चोट भी आई है।

प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर अजय कुमार नौडियाल ने कहा– हमले की वजहें वही (विधायक) बेहतर जानते हैं। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊपर आरोप लगाते हुए कहा– वे एक स्कूल का नाम बदलने के लिए ऑफिस आए थे। हमने उनसे कहा कि नाम तभी बदला जा सकता है जब राज्य सरकार के लेवल से ऑर्डर आ जाएं। हमने बस इतना ही कहा था। अफसर का आरोप है कि विधायक के साथ करीब 20–25 लोग और भी थे। शुरू से ही गाली–गलौज करते हुए आए और कमरा बंद कर दिया। मेरे सिर पर चोटें लगी हैं। आंख के अंदर भी हैं। ऑफिस के अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। शुरू से ही गाली–गलौज करते हुए आए और कमरा बंद कर दिया। विधायक जी के साथ कमरे के अंदर 20–25 लोग और भी थे। घटना के बाद कर्मचारियों में दहशत और भारी आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि किसी मुद्दे पर असहमति थी तो इसका समाधान प्रशासनिक स्तर पर निकाला जा सकता था। इस तरह सरकारी दफ्तर में घुसकर मारपीट और हमला करना अस्वीकार्य है। इस घटना के बाद से सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों का अलग–अलग बयान है। एक तरफ शिक्षा निदेशक नौडियाल का कहना है कि विधायक ने खुद दरवाजा बंद कराया था। वहीं विधायक पक्ष का कहना है कि वो लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी कर्मचारियों ने बाहर से गेट बंद कर दिया। दरवाजा किसने बंद किया, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। ये पूरा मामला रायपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगे शिलापट्ट पर नाम बदलने से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसको लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है।

पिटकुल एमडी की नियुक्ति पर यूकेडी ने उठाए सवाल

देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल ने पिटकुल के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को पार्टी की केंद्रीय महामंत्री किरन रावत केन्द्रीय कार्यालय कचहरी रोड में हुई प्रेसवार्ता में कहा कि उच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को पारित आदेश में प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए सरकार को अंतरिम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नियुक्ति अधिनियम के नियम 9 ए व 9ए(4) के उल्लंघन का मामला उठाया गया था, जिसे न्यायालय ने प्रथम दृष्टया स्वीकार किया। न्यायालय ने चयन प्रक्रिया और तकनीकी अर्हता पर सवाल खड़े किए हैं। यूकेडी ने आरोप लगाया कि बिना आवश्यक योग्यता के इतनी महत्वपूर्ण नियुक्ति करना गंभीर अनियमितता है। पार्टी ने मांग की कि यदि सरकार पारदर्शी है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे वित्तीय क्षति की वसूली की जाए। पार्टी ने चेतावनी दी कि मामले में ठोस कदम न उठाए जाने पर पिटकुल और सचिवालय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में केंद्रीय महामंत्री संगठन गणेश क'ला,राजेंद्र सिंह बिष्ट, केंद्रीय मंत्री रघुवीर सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष प्रवीण रमोला, संगठन मंत्री कपिल कुमार, रीता देवी, संतोष नौटियाल, सुमन नेगी मौजूद रहे।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com